Regd. No. CHD/0093/2015–2017

# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 22, 2017 (SRAVANA 30, 1939 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

आबकारी तथा कराधान विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 22 अगस्त, 2017

**संख्या 76/एसटी–2.**– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, –

(i) सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (2) में, ''माल परिवहन अभिकरण (जीटीए)'' शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, '',जिसने 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का भुगतान नहीं किया है,'' शब्द, चिहन, और अंक रखे जाएंगे;

(ii) सारणी के अंत में, व्याख्या में, खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(ड़) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के उपबंधों के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत ''सीमित दायित्व भागीदारी'' को किसी भागीदारी फर्म या किसी फर्म के रुप में भी माना जाएगा।''।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
**Notification**
The 22nd August, 2017

**No. 76/ST-2** - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(i) in the Table, against serial number 1,in column (2), after the words and brackets "goods transport agency (GTA)" the words, signs and figure ",who has not paid state tax at the rate of 6%," shall be inserted;

(ii) in the Explanation, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) A "Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.".

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

55580—C.S.—H.G.P., Chd.